किसानों के लिए आधुनिक कृषि विपणन मंच

देवेन्द्र कुमार वर्मा

"कृषि विपणन को मोटे तौर पर पारंपरिक और आधुनिक कृषि विपणन में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारंपरिक विपणन में किसान अपनी उपज सीधे थोक विक्रेताओं या बिचौलियों को बेचते हैं, जो फिर उत्पादों को मूल्य श्रृंखला में आगे बेचते हैं। बिचौलिए अक्सर किसानों से कम मूल्य पर उपज खरीदते हैं और उसे उच्च मूल्य पर बाजार में बेचते हैं। आधुनिक विपणन में उन्नत विपणन विधियां और प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जो किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करती हैं और उन्हें सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करती हैं। आधुनिक विपणन में ई-नाम, सुपरमार्केट और अनुबंध खेती जैसी विधियां शामिल हैं, जो न केवल किसानों के लिए नए अवसर लाती हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। यह लेख आधुनिक कृषि विपणन मंचा ई-नाम के महत्व को प्रदर्शित करता है, जो किसानों के लिए लाभ के द्वार खोल रहा है।"

भारत में कृषि विपणन एक जटिल और बहुपक्षीय प्रक्रिया है, जो सिर्फ कृषि उत्पादों के उत्पादन से शुरू नहीं होती, बल्कि यह समग्र बाजार संरचना और किसानों की आय को बेहतर बनाने के लिए कई चरणों से गुजरती है। यह प्रक्रिया किसानों को यह तय करने में मदद करती है कि कौन सी फसल उगानी चाहिए, किस समय उगानी चाहिए और किस प्रकार की खेती सबसे लाभकारी हो सकती है। ऐसे निर्णय आमतौर पर बाजार की मांग, लागत, मौसम की परिस्थितियों और किसान के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हैं।

सहायक आचार्य,कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय नौगांवा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

भारत में कृषि विपणन की पूरी प्रक्रिया किसानों के लिए अवसर प्रदान करती है कि वे अपनी फसल को बेहतर मूल्य पर बेच सकें और उपभोक्ताओं के लिए यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद मिलें। यह प्रक्रिया न केवल कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।

ई-नाम एक डिजिटल मंच है, जो किसानों को देशभर की मंडियों में अपनी उपज बेचने का अवसर प्रदान करता है। यह एक स्मार्ट और पारदर्शी तरीका है, जिसके माध्यम से किसान अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। आज ई-नाम किसानों के लिए कृषि विपणन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सशक्त विकल्प बन गया है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को अपनी कृषि उपज को डिजिटल तरीके से बेचने, खरीदने और व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है।

ई-नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसे भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्शियम द्वारा लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में कृषि उत्पादों के लिए 'एक राष्ट्र, एक बाजार' के सिद्धांत के तहत मौजूदा मंडियों को एक साझा ऑनलाइन मंच पर जोड़ना है।

ई-नाम से जुड़ने के लिए किसानों को केवल एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होता है। पंजीकरण के बाद उन्हें सीधे मंडी में व्यापार करने की सुविधा मिलती है। यह प्रक्रिया सहज और आसान है, जिससे किसान आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

ई-नाम पर कृषि उत्पाद का विपणन

ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि उपज बेचने के लिए किसान को अपने उत्पाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मापदंड दर्ज या अपलोड करने होते हैं। इसका उद्देश्य खरीददार को सही जानकारी प्रदान करना और ग्रेडिंग, मूल्य निर्धारण तथा लेन-देन को पारदर्शी बनाना है। किसान को अपनी उपज का नाम (जैसे-गेहूं, धान, प्याज, टमाटर आदि) सही तरीके से दर्ज करना होता है। ग्रेडिंग के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एगमार्क या अन्य क्वालिटी ग्रेड सिस्टम का उपयोग किया जाता है।

किसान को यह भी बताना होता है कि वह कितनी मात्रा (क्विंटल/कि.ग्रा.) में उपज बेचने के लिए तैयार है। फसल की किस्म, नमी की मात्रा और भौतिक विशेषताएं जैसे-रंग, आकार, टूटे दाने या कंकड़-मृदा की मात्रा आदि, इन जानकारियों के आधार पर ही मूल्य निर्धारण और लेन-देन किया जाता है।

ई-नाम प्लेटफॉर्म पर डिजिटल भुगतान और लेन-देन की सुविधा उपलब्ध है। इससे किसानों को सुरक्षित और त्वरित भुगतान मिलता है। पारंपरिक विपणन में बिचौलियों और मंडी एजेंटों के कारण भुगतान में अक्सर देरी हो जाती थी, लेकिन ई-नाम के माध्यम से भुगतान

सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरण हो जाता है। इससे किसानों को समय पर और बिना किसी देरी के राशि प्राप्त होती है।

हर लेन-देन और मूल्य निर्धारण पारदर्शी तरीके से होता है, जिससे किसान विभिन्न मंडियों और व्यापारियों के मूल्य की तुलना कर सकते हैं और अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य पा सकते हैं। डिजिटल रिकॉर्डिंग के माध्यम से लेन-देन का डेटा भविष्य में ऋण आवेदन, बीमा दावे और अन्य वित्तीय गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है, जिससे किसानों के लिए वित्तीय ट्रैकिंग और आर्थिक सहायता प्राप्त करना आसान हो जाता है।

ई-नाम प्लेटफॉर्म किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। यह उन्हें व्यापक बाजार तक पहुंच तथा बेहतर मूल्य प्रदान करता है। इसके साथ ही यह मंच कृषि विपणन में पारदर्शिता, समय पर भुगतान एवं आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करता है। इस तरह, ई-नाम भारतीय कृषि विपणन को नई दिशा दे रहा है।

चुनौतियां

ई-नाम ने भारतीय कृषि विपणन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इसके बावजूद कुछ चुनौतियां और समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, जो किसानों और अन्य संबंधित पक्षों को प्रभावित करती हैं।

सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ई-नाम का सही उपयोग करने के लिए इंटरनेट और स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। बहुत से किसान इनका इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हैं। इसके साथ ही, प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने के लिए किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

कई किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनुभव नहीं है और उन्हें यह पता नहीं होता कि कैसे अपने उत्पादों को सूचीबद्ध करें, मूल्य देखें तथा भुगतान प्राप्त करें। जागरूकता की कमी के कारण कई किसान ई-नाम की विशेषताओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते और पारंपरिक बाजारों की ओर लौट जाते हैं।

सभी मंडियां अभी तक ई-नाम से पूरी तरह जुड़ी नहीं हैं। कुछ राज्यों और मंडियों में यह प्रणाली पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। इससे विपणन की पहुंच सीमित रहती है और किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

हालांकि ई-नाम का उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका को कम करना है। कुछ मामलों में वे अभी भी पारंपरिक तरीके से कार्य करते हैं। बिचौलिए कभी-कभी ई-नाम का उपयोग किए बिना किसानों से सीधे सौदे करने की कोशिश करते हैं।

इसके अलावा, भंडारण सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। जब किसान अपनी उपज को मंडी में संग्रहित नहीं कर पाते, तो उन्हें इसे जल्दी बेचने के लिए कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाने में भी कुछ कठिनाइयां हैं। प्रत्येक राज्य में मंडी शुल्क, लेन-देन के तरीके और कृषि उत्पादों के वर्गीकरण में भिन्नताएं होती हैं। इससे किसानों को अपने राज्य और अन्य राज्यों के बीच अंतर समझने में मुश्किल होती है तथा यह ई-नाम के उद्देश्य को पूरी तरह साकार करने में बाधा डालता है। ■

बाजार तक सीधी पहुंच

ई-नाम किसानों को सीधे बाजारों से जोड़कर उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करवाने में मदद करता है और बिचौलियों की भूमिका को कम करता है। इस प्लेटफॉर्म पर किसानों को उनके उत्पादों के लिए वास्तविक और पारदर्शी मूल्य का ज्ञान होता है। इसके माध्यम से किसान अपने उत्पाद को जानकर उसे उत्पाद की मंडी में उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। इससे मंडी प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ती है और बिचौलियों द्वारा किसानों को कम मूल्य पर उत्पाद बेचने के दबाव को कम किया जा सकता है। ई-नाम पर किसान सीधे खरीदारों और बाजारों से जुड़ सकते हैं, चाहे वे थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता या अन्य कृषि उत्पादक हों। इसके माध्यम से किसान मंडी से बाहर अपनी उपज सीधे ग्राहकों या व्यापारियों को भी बेच सकते हैं, जिससे उनका लाभ बढ़ता है और बाजार क्षेत्र विस्तृत होता है। इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी सभी कृषि उपज जैसे-अनाज, फल, सब्जियां या अन्य कृषि उत्पाद भी बेच सकते हैं। यह विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं और जिनकी मंडियों तक पहुंच सीमित होती है।

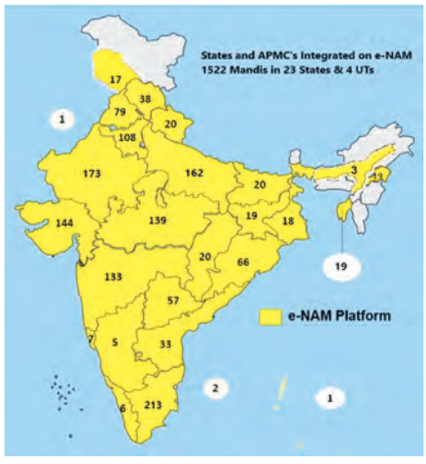

देश में ई-नाम प्लेटफार्म की राज्यवार संख्या

सारणी 1. देश में ई-नाम बाजार की स्थिति

क्र. सं.	राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश	कुल संख्या (मंडियां)
1	अंडमान और निकोबार	1
2	आंध्र प्रदेश	33
3	असोम	3
4	बिहार	20
5	चंडीगढ़ (केन्द्र शासित प्रदेश)	1
6	छत्तीसगढ़	20
7	गोवा	7
8	गुजरात	144
9	हरियाणा	108
10	हिमाचल प्रदेश	38
11	जम्मू और कश्मीर (केन्द्र शासित प्रदेश)	17
12	झारखंड	19
13	कर्नाटक	5
14	केरल	6
15	मध्य प्रदेश	139
16	महाराष्ट्र	133
17	नगालैंड	19
18	ओडिशा	66
19	पुदुचेरी (केन्द्र शासित प्रदेश)	2
20	पंजाब	79
21	राजस्थान	173
22	तमिलनाडु	213
23	तेलंगाना	57
24	त्रिपुरा	19
25	उत्तर प्रदेश	162
26	उत्तराखंड	20
27	पश्चिम बंगाल	18

सारणी 2. ई-नाम के अंतर्गत आने वाले उत्पाद

उत्पाद समूह	कुल संख्या
खाद्यान्न/अनाज	35
तिलहन	15
फल	46
सब्जियां	59
मसाले	17
अन्य	52
कुल वस्तु	224